

पांच हिस्सों में बंटा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

■ ऊर्जा विभाग ने जारी की अधिसूचना ■ पांच साल में 14099 करोड़ रुपये सहायता देगी सरकार

संवादप्रता ■ पटना

बीजे शुक्रवार को राज्य कैबिनेट से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन की स्मृति मिलने के बाद ऊर्जा विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी. एक वर्ष का से बिजली बोर्ड पांच भागों में काम करेगा. इनमें एक सोलरिंग कंपनी होगी और शेष में एक संचरण, एक लवण व दो वितरण के लिए उत्तर व दक्षिण क्षेत्र की कंपनियों होंगी. बिजली बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष प्रभात कुमार राय को पांचों कंपनियों का अध्यक्ष बनाया गया है.

कर्मचारियों की सेवा रहेगी बरकरार

पुनर्गठन के बावजूद राज्य सरकार सहायता देती होगी. पांच सालों में सरकार बोर्ड को पुनर्गठित पांचों कंपनियों पर 14,099 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पांच हिस्से में बंटने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने वाक्ये के अनुसार कर्मचारियों को सेवा शर्तों को बरकरार रखा है. पांच कंपनियों के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना बीजे महीने की जारी हो गयी थी. कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर यमला भंडा था, जिस पर 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी थी. सोए से मिली स्मृति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष

ये हैं पांचों कंपनियां

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
 निदेशक अध्यक्ष/निदेशक : प्रकाश लखिपति सिंह, उद्योग, बिहार
 उपाध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
 निदेशक अध्यक्ष/निदेशक : प्रकाश लखिपति सिंह, उद्योग, बिहार
 उपाध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
 निदेशक अध्यक्ष/निदेशक : प्रकाश लखिपति सिंह, उद्योग, बिहार
 उपाध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार



राज्य बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
 निदेशक अध्यक्ष/निदेशक : प्रकाश लखिपति सिंह, उद्योग, बिहार
 उपाध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार

पश्चिम निदेशक : लखनऊ, उद्योग, बिहार
 अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार
पूर्व निदेशक : मुंबई, उद्योग, बिहार
 अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार

दक्षिण निदेशक : चेन्नई, उद्योग, बिहार
 अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार
उत्तर निदेशक : देहरादून, उद्योग, बिहार
 अध्यक्ष : प्रभात कुमार राय, उद्योग, बिहार

बोर्ड का इतिहास

- स्थापना : 25 मार्च, 1958
- काम शुरू हुआ : एक अप्रैल, 1958
- कार्यरत कर्मचारी : 10 हजार से अधिक
- सकल : सत, जंगल : 16 व विद्युत आपूर्ति प्रकल्प : 65
- वर्ष 2003 में विद्युत अधिनियम पारित होने के बाद बोर्ड पर विभाजन का खतरा
- 2012 में बत पर अलग हुआ और बोर्ड विद्युत पांच हिस्सों में बंट गया

लाया गया. कैबिनेट से पारित होने के बाद शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी.

पांच साल में होना होगा आत्मनिर्भर

राज्य सरकार विद्युत बोर्ड को 180 करोड़

रुपये प्रतिवर्ष के बिलान में सालाना 2160 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सहायता दे रही थी. पुनर्गठन के पांच साल तक सरकार 14099 करोड़ रुपये इन कंपनियों पर खर्च करेगी. पांच साल के बाद राज्य सरकार इन कंपनियों को कोई सहायता नहीं देनी होगी. सरकार को

उम्मीद है कि पुनर्गठन से मिलती कंपनियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा.

इसमें इन पांचों कंपनियों के प्रबंधन को पूरी तरह से प्रोत्साहित बनाया जायेगा. ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से एक

नीति भी बनायी गयी है. सरकार ने अपने किये गये वाक्ये के अनुसार वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का पूरा खयाल रखा है. कर्मचारी संगठनों की ओर से किये गये वाक्ये के अनुसार सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी मुहर लगायी है.